उत्तराखंड में खुली महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की राह

विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 देहरादून में संपन्न

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 28 | मूल्य 15 रुपये | 30 नवम्बर-06 दिसंबर, 2025

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027

तिथियां और स्नान पर्व घोषित

वर्ष 15 | अंक 28

दिव्य हिमगिरि

30 नवम्बर-06 दिसंबर, 2025

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

हिरासत में मौत: बढ़ता आंकडा

पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न हिस्सों में हिरासत में मौत की घटनाओं का मसला चिंताजनक रूप से उभर कर सामने आया है। जांच एजेंसियों का काम आपराधिक मामलों में आरोपियों को न्याय के कठघरे में लाना है। दोष साबित करने के लिए सबूत जुटाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। ऐसे में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करना जांच प्रक्रिया का हिस्सा है। मगर इस दौरान आरोपी की सुरक्षा का दायित्व भी संबंधित जांच एजेंसी का ही होता है। सवाल है कि अगर पुलिस या अन्य जांच एजेंसियां अपने इस दायित्व को सही तरीके से निभा रही हैं, तो आए दिन हिरासत में मौत के मामले क्यों सामने आ रहे हैं? जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता क्यों नहीं बरती जा रही है। जाहिर है कि इस मामले में कहीं न कहीं लापरवाही और मनमानी की जा रही है, जिस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी कड़ा संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने राजस्थान में आठ माह के भीतर पुलिस हिरासत में ग्यारह लोगों की मौत हो जाने का हवाला देते हुए मंगलवार को कहा कि हिरासत में हिंसा एवं मौत व्यवस्था पर एक धब्बा है और देश अब इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। यह सच है कि लोग जांच एजेंसियों पर कम और न्यायपालिका पर ज्यादा भरोसा करते हैं। मगर न्याय प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही अगर किसी आरोपी की हिरासत में मौत हो जाती है, तो निश्चित रूप से न्याय की भावना को चोट पहुंचती है। सर्वोच्च न्यायालय ने मानवाधिकारों के हनन को रोकने के लिए वर्ष 2018 और 2020 में अलग-अलग आदेशों में पुलिस थानों, केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और राष्ट्रीय जांच एजेंसी सहित अन्य जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे तथा रिकार्डिंग उपकरण लगाने को कहा था। इस व्यवस्था से जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता आना स्वाभाविक था, लेकिन इस पर अमल करने में भी कई स्तरों पर कोताही बरती जा रही है। कई पुलिस थानों में सीसीटीवी न लगे होने या उनके बंद होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि जांच एजेंसियां हिरासत में मानवाधिकारों की रक्षा को लेकर गंभीर नहीं हैं। शीर्ष अदालत ने इस मसले पर भी संज्ञान लिया है और अब तक अनुपालन हलफनामे दाखिल नहीं करने वाले राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को इसके लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक रपट के मुताबिक, वर्ष 2017-2022 तक पांच वर्षों में देश भर में पुलिस हिरासत में 669 लोगों की मौत हुई। यह स्थिति पुलिस हिरासत में लोगों की सुरक्षा को लेकर वास्तव में गंभीर चिंता पैदा करने वाली है। इस तरह के मामलों में शारीरिक प्रताड़ना, जरूरी चिकित्सा सेवाएं मुहैया न कराना या आत्महत्या जैसे कारण हो सकते हैं। नियमानुसार किसी भी मामले की जांच के दौरान मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन इस तरह की शिकायतें आए दिन सामने आती रही हैं। ऐसे में इस बात पर गौर करना जरूरी है कि हिरासत में मौत की घटनाओं पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी सिर्फ न्यायालय की नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्यों सरकारों को भी इस पर तत्परता एवं गंभीरता दिखानी होगी। संबंधित कानूनों और न्यायालय के निर्देशों पर प्रभावी तरीके से अमल हो, इसका दायित्व सरकार का ही है। अगर हिरासत में किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसके लिए जवाबदेही तय कर दोषी कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

शीतकाल के लिए बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट

अलकनंदा घाटी में हल्की ठंडक और ऊंची पहाड़ियों पर जमती बर्फ के बीच मंगलवार सुबह बद्रीनाथ धाम का वातावरण अद्भुत शांति और भक्ति से भर गया। घंटे-घड़ियाल की ध्वनि, पुष्प-वर्षा और ओजपूर्ण वेद मंत्रों के बीच बाबा बद्रीविशाल के कपाट अगले छह महीनों के लिए शीतकालीन प्रवास पर विधि-विधान के साथ बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने के साथ ही अखंड ज्योति नीतिवास के लिए पांडुकेश्वर स्थित योगध्यान बदरी मंदिर की ओर ले जाई गई, जहां आगामी छह महीने पूजा-अर्चना निरंतर चलती रहेगी। धाम की ऊंचाइयों में उतरती कड़ाके की ठंड और धीरे-धीरे शांत होते कदमों के बीच यह दृश्य एक बार फिर याद दिला गया कि बद्रीनाथ केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि हर भक्त के मन में बसने वाली अमिट आस्था का सजीव स्वरूप है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

अलकनंदा घाटी की ठंडी दोपहर में मंगलवार को ठीक 2 बजकर 56 मिनट पर वह पवित्र क्षण आया, जब मंत्रोच्चार, घंटे-घड़ियाल और पुष्प-वर्षा के बीच बद्रीनाथ धाम के कपाट छह माह के शीतकालीन प्रवास के लिए विधि-विधान के साथ बंद कर दिए गए। ऊंची पहाड़ियों पर जमी बर्फ और ठंड की लहरों के बीच मंदिर परिसर एक अलौकिक आभा से दमक रहा था। धाम को बारह कुंतल फूलों से सजाया गया था, और इस दिव्यता के बीच हजारों श्रद्धालु उस पल के साक्षी बने, जब बाबा बद्रीविशाल को भावपूर्ण विदाई दी गई। यात्रा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की भीड़ कुछ अलग ही भाव में दिखाई दी। किसी की आंखें नम थीं, कोई दूर खड़े जुड़े हाथों से अंतिम प्रणाम कर रहा था, तो कोई अगले वर्ष पुनः दर्शन की आशा लिए मौन बैठा था। भक्ति और विरक्ति का यह अद्भुत संगम पूरे परिसर में गूंज रहा था। इस वर्ष यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ धाम में दर्शन किए, और कपाट बंद होने के इस क्षण ने मानो उनकी पूरी यात्रा का सार एक ही भाव में समेट दिया। आस्था अडिग है, और दर्शन का इंतजार कभी थमता नहीं। कपाट बंद होने के साथ ही अखंड ज्योति को शीतकालीन गद्दी स्थल पांडुकेश्वर स्थित योगध्यान बदरी मंदिर की ओर ले जाया गया, जहां आगामी छह महीनों तक नियमित पूजा-अर्चना चलती रहेगी। बद्रीनाथ धाम में अब सन्नाटा और बर्फ की चादर छा जाएगी, लेकिन श्रद्धालुओं के मन में बसे भगवान बद्री विशाल के प्रति प्रेम और विश्वास की ऊष्मा हर कठिन मौसम से ऊपर बनी रहेगी। जब आखिरी बार 'जय बद्री विशाल' का उद्घोष गूंजा, तो घाटी भर में मानो एक भावनात्मक कंपन फैल गया। यह सिर्फ कपाट बंद होने का आयोजन नहीं था, बल्कि उस परंपरा का स्मरण भी, जिसने सदियों से उत्तराखंड की सांस्कृतिक धारा को जीवित रखा है। अगले छह महीने धाम शांत रहेगा, पर भक्तों का विश्वास उसी तरह जलता रहेगा, अगली यात्रा के प्रथम दर्शन तक। दूसरी ओर, कपाट बंद होने के बाद शीतकाल में शुरू होने वाली परंपराएँ भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। पांडुकेश्वर स्थित योगध्यान बदरी में अब पूरे छह महीने भगवान बद्रीविशाल की पूजा-अर्चना जारी रहेगी। यहां स्थानीय परिवार हर दिन मिलकर पूजा में सहयोग करते हैं। कोई प्रसाद बनाता है, कोई फूल चढ़ाता है और कोई दीप सजाता है। गांव के लोग बताते हैं कि इन छह महीनों में आध्यात्मिक वातावरण इतना गहरा होता है कि पूरा गांव एक मंदिर की तरह लगता है। बच्चे सुबह-सुबह शंख बजाते हैं, बुजुर्ग भगवान की आरती गाते हैं और महिलाएं पूरे गांव में दीप-श्रृंखला सजाती हैं। ऐसा माना जाता है कि बद्रीनाथ की पवित्रता शीतकाल में पूरी तरह इसी गांव में उतर आती है। भक्तों के लिए भी यह समय विशेष महत्व रखता है। वे मानते हैं कि धाम भले बर्फ में ढका हो, पर भगवान उनके बीच यहीं योगध्यान बदरी में विराजमान रहते हैं। छह महीने बाद जब धाम फिर खुलेगा, तो यह पूरा क्षेत्र फिर से जीवन से भर उठेगा, लेकिन इन शांत महीनों में भगवान की उपस्थिति भक्तों के मन और नदी की धारा दोनों में एक पवित्र स्थिरता बनाए रखती है। पूरे यात्रा सीजन में दिन-रात सेवा में जुटे चमोली पुलिस के जवानों ने इस अवसर पर अपने साथियों के साथ एक स्मृति फोटो खिंचवाई, जिससे इस अध्याय को यादगार बनाया जा सके। यात्राकाल के दौरान पुलिस जवानों ने लगातार बदलते मौसम, ऊंचाई और भीड़-प्रबंधन जैसी चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने श्रद्धालुओं की सुरक्षा, आपातकालीन सहायता, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाया। कपाट बंद होने के इस क्षण को जवानों ने कैमरे में कैद किया। उन्होंने इसे अपने जीवन भर की प्रेरणा के रूप में संजोने की बात कही। चमोली पुलिस के जवानों ने इस यात्रा अवधि में सुरक्षा व्यवस्था के

साथ-साथ सेवा-भाव और संवेदनशीलता का भी उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। बद्रीनाथ धाम जैसे पवित्र स्थल पर सेवा करना उनके लिए सम्मान का विषय रहा। जवानों ने बताया कि यह तस्वीर उनकी टीम भावना, समर्पण और त्याग का प्रतीक है। यह उन्हें भविष्य में भी सेवा के मार्ग पर प्रेरित करती रहेगी। धाम के कपाट बंद होने के साथ ही यात्रा सीजन का सफल समापन हुआ। इस दौरान पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थानीय प्रशासन और श्रद्धालुओं ने सराहा।

इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को खुले थे

इस साल बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई 2025 को खुले और चारधाम यात्रा के प्रारंभिक दिन से ही श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या दर्शन के लिए जुटी। मंदिर समिति के अनुसार इस यात्रा सत्र में लगभग 16.6 लाख श्रद्धालु केवल बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने आए। यह आंकड़ा पिछले साल की तुलना में बढ़ा हुआ था और दिखाता है कि श्रद्धा और आस्था आज भी उतनी ही प्रबल है। खुलने के दिन से ही घाटी में भक्तों की भीड़ रही, सुबह से लेकर शाम तक दर्शनार्थियों की लंबी कतार लगी रही। धाम की व्यवस्थाओं के लिए मंदिर समिति, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों ने समन्वित प्रयास किए, ताकि तीर्थयात्रियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन की सुविधा उपलब्ध हो। मंदिर परिसर को फूलों और दीपों से सजाया गया और सुबह-शाम की आरती, भजन-कीर्तन और वेद मंत्रों की ध्वनि ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक रूप से प्राणवान बना दिया। श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। कई परिवारों ने पूरे वर्ष की तैयारी कर बद्रीनाथ यात्रा की, पर्वतीय कठिन मार्गों और मौसम की चुनौतियों के बावजूद अपनी श्रद्धा को अडिग रखा। यात्रा के दौरान भक्त विभिन्न पूजा-अर्चना में भाग लेते रहे और धाम के चारों ओर धार्मिक गतिविधियों का जीवंत दृश्य देखने को मिला। मंदिर समिति के अनुसार, इस बार यात्रा का मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहा, जिससे भक्त सुरक्षित और सहज रूप से दर्शन कर सके। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले होने के साथ ही पूरे चारधाम यात्रा का आरंभ हुआ, और श्रद्धालुओं के लिए यह समय केवल दर्शन का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक अनुभव का भी अद्वितीय अवसर रहा। श्रद्धालु गहन आस्था और भक्ति के साथ भगवान बद्रीविशाल के दर्शन कर अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और मानसिक शांति अनुभव कर रहे थे।

माधो सिंह भंडारी सामूहिक खेती योजना बनी वरदान

सूबे में सामूहिक खेती से आबाद हो रहे बंजर खेत

2400 किसानों के जरिये 1235 एकड़ पर हो रही खेती

सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित माधो सिंह भण्डारी सहकारी सामूहिक खेती योजना बंजर खेतों के लिये वरदान साबित हो रही है। इस योजना से बंजर हो चुके खेत न सिर्फ सरसब्ज हो रहे हैं बल्कि किसानों की आजीविका को भी सुदृढ़ कर रही है। वर्तमान में इस योजना के तहत 1235 एकड़ भूमि पर सामूहिक खेती की जा रही है, और प्रदेशभर के 24 सहकारी समितियां से जुड़े लगभग 2400 किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

राज्य सरकार ने प्रदेश में सामूहिक सहकारी खेती का सशक्त मॉडल तैयार कर पलायन से बंजर पड़े खेतों को सरसब्ज किया है। सरकार ने माधो सिंह भण्डारी सहकारी समूहिक खेती योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में बंजर खेतों की पहचान कर 4750 एकड़ अनुपयुक्त भूमि को आबाद करने का लक्ष्य रखा गया है। जिसके तहत 70 क्लस्टरों का चयन किया गया, जिसमें से 24 क्लस्टरों में चयनित सहकारी समितियों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर आधुनिक तकनीक का उपयोग कर सामूहिक खेती की जा रही है। जिसमें नैनीताल व पौड़ी जनपद में 4-4, अल्मोड़ा, रूद्रप्रयाग, हरिद्वार चमोली व देहरादून में 1-1 तथा चम्पावत जनपद में 2 सहकारी समितियां के माध्यम सें सामूहिक खेती की जा रही है। इन कलस्टरों में मिलेट्स, बेमौसमी सब्जियां, दालें, फल, औषधीय और सुगंधित पौधों की फसल, चारा फलस के साथ ही व्यावसायिक खेती की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस योजना के तहत कृषि पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन समितियों के माध्यम से वर्तमान में 1235 एकड़ भूमि पर सामूहिक खेती की जा रही है, जिससे लगभग 2400 किसान सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहे हैं। माधो सिंह भण्डारी सहकारी समूहिक खेती योजना से न सिर्फ प्रदेश कीं अनुपयोगी भूमि पुनः उपजाऊ हो रही है, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से समृद्धि कर रही है। इसके अलावा यह योजना लोगों को रिवर्स माइग्रेशन के लिये भी प्रोत्साहित कर रही है। सहकारिता विभाग का लक्ष्य है कि आगामी वर्षो में सामूहिक खेती के इस मॉडल को और अधिक विस्तार दिया जायेगा। जिससे पलायन प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आधारित रोजगार को बढ़ावा मिल सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिल सके।

> माधो सिंह भण्डारी सहकारी समूहिक खेती योजना प्रदेश के ग्रामीण विकास व कृषि पुनर्जागरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। यह योजना न केवल बंजर भूमि को उपजाऊ बना रही है बल्कि किसानों को संगठित कर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है।
>
> *-डॉ. धन सिंह रावत*

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027
तिथियां और स्नान पर्व घोषित

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तिथियां और स्नान पर्व अब आधिकारिक रूप से सार्वजनिक कर दिए गए हैं। यह भव्य आयोजन 14 जनवरी से शुरू होकर 20 अप्रैल तक चलेगा, जो कुल 97 दिनों तक श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों के लिए आस्था और अध्यात्म का महासंगम रहेगा। इस दौरान दस प्रमुख स्नान होंगे, जिनमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु गंगा के पावन तट पर नहाने और अपने मन, शरीर तथा आत्मा को शुद्ध करने के लिए आएंगे। इस महत्वपूर्ण घोषणा से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हरिद्वार में सभी 13 अखाड़ों के आचार्यों और प्रमुख साधु-संतों के साथ बैठक की, जिसमें अर्धकुंभ 2027 के आयोजन की तैयारियों, सुरक्षा, श्रद्धालु सुविधा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आयोजनों को सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सहज बनाने पर विशेष जोर दिया। हरिद्वार अर्धकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है, बल्कि यह संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिकता का विशाल मंच है। इस आयोजन में न केवल पवित्र स्नान होते हैं, बल्कि धार्मिक प्रवचन, साधना, योग और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात और श्रद्धालु सुविधाओं के विशेष इंतजाम भी शुरू कर दिए हैं, ताकि हर व्यक्ति पूर्ण रूप से आस्था के इस महापर्व का अनुभव कर सके। 2027 का अर्धकुंभ हरिद्वार को फिर से विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाएगा और श्रद्धालुओं के लिए जीवनभर का अनुभव साबित होगा।

हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 की तिथियां और स्नान पर्व आधिकारिक रूप से घोषित कर दिए गए हैं। यह भव्य आयोजन 14 जनवरी से 20 अप्रैल तक चलेगा, यानी कुल 97 दिनों तक देश-विदेश के श्रद्धालु गंगा के पावन तट पर आस्था और अध्यात्म का अनुभव करेंगे। इस दौरान दस प्रमुख स्नान आयोजित किए जाएंगे, जो धार्मिक आस्था और संस्कृति का सबसे बड़ा संगम साबित होंगे। अर्धकुंभ की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल हरिद्वार में सभी 13 अखाड़ों के आचार्यों और प्रमुख साधु-संतों के साथ बैठक की। बैठक में अर्धकुंभ के आयोजन, श्रद्धालु सुविधा, सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने इस दौरान आयोजन को सुव्यवस्थित और श्रद्धालुओं के लिए सहज

बनाने पर जोर दिया। हरिद्वार अर्धकुंभ केवल एक धार्मिक मेला नहीं है। यह संस्कार, संस्कृति और आध्यात्मिकता का विशाल मंच है। आयोजन के दौरान धार्मिक प्रवचन, साधना, योग, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परंपरागत रीतियां भी आयोजित की जाएंगी। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सुरक्षा, यातायात और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर लिया है। अर्धकुंभ के दौरान लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे, जिससे न केवल धार्मिक बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह महापर्व राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हरिद्वार को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाने का अवसर होगा। स्नानों की सूची इस प्रकार है। 14 जनवरी मकर संक्रांति (प्रथम स्नान), 6 फरवरी मौनी अमावस्या, 11 फरवरी वसंत पंचमी, 20 फरवरी माघ पूर्णिमा, 6 मार्च महाशिवरात्रि (पहला शाही/अमृत स्नान), 8 मार्च फाल्गुण अमावस्या (दूसरा शाही स्नान), 7 अप्रैल नव संवत्सर (हिंदू नया साल), 14 अप्रैल मेष संक्रांति / बैसाखी (तीसरा शाही स्नान), 15 अप्रैल श्रीराम नवमी, और 20 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा (समापन स्नान)। कुल 10 स्नानों में से तीन को विशेष रूप से 'शाही/अमृत स्नान' के रूप में घोषित किया गया है, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इस बार अर्धकुंभ का आयोजन आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा, ताकि हर उम्र के श्रद्धालु सुरक्षित और सहज रूप से इस दिव्य अनुभव का हिस्सा बन सकें। दस प्रमुख स्नान और 97 दिनों के कार्यक्रम को देखते हुए, अधिकारियों ने यातायात और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं, ताकि श्रद्धालु और आम नागरिक दोनों के लिए आयोजन सुगम और सुरक्षित हो। हरिद्वार अर्धकुंभ 2027 न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह सांस्कृतिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना को बढ़ावा देने वाला महापर्व भी साबित होगा। मेला प्रशासन ने तय किया है कि 2027 के अर्धकुंभ के लिए एक एआई. आधारित कंट्रोल रूम स्थापित किया जाएगा। पूरे मेला क्षेत्र में 27,500 सीसीटीवी कैमरों का नेटवर्क लगाया जाएगा, ताकि भीड़-प्रबंधन, सुरक्षा और निगरानी सुचारू रूप से हो सके। कंट्रोल रूम के साथ पुराने भवन को अपग्रेड किया जाएगा, और एक नया भवन बनाया जाएगा। जिसमें हेलीपैड, आपातकालीन व्यवस्थाएं और आधुनिक निगरानी सुविधाएं होंगी। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार ने अर्धकुंभ को "महाकुंभ जितना भव्य" बनाने की योजना बनाई है। इस दिशा में, मेले क्षेत्र में नए घाटों का निर्माण और मौजूदा घाटों का सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा, पल, सड़कों, पुल-निर्माण, पार्किंग, यातायात प्रबंधन, सफाई, स्वच्छता, कूड़ा-प्रबंधन आदि की तैयारियाँ भी चल रही हैं। ताकि श्रद्धालुओं व साधु-संतों के लिए सुविधाजनक, सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल तैयार हो सके।

हरिद्वार कुंभ मेला 2021 में आयोजित हुआ था

मेला के शुरुआती दिनों में ही, पहली स्नान पर करीब 7,11,000 श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी घाट पर पवित्र गंगा में डुबकी लगाई थी। लेकिन कोविड-19 के बीच आयोजित इस मेला में स्वास्थ्य-निर्देशों (जैसे मास्क, सोशल-डिस्टेंसिंग) का बहुत भंग देखा गया। अनेक श्रद्धालु नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। 10-14 अप्रैल 2021 के बीच, मेला क्षेत्र में किए गए परीक्षणों में 1,701 लोग कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए। यह संख्या आरटी-पीसीआर व एंटीजन दोनों प्रकार के परीक्षणों में मिली थी। साधुओं में भी संक्रमण

2027 का अर्धकुंभ "पुर्ण कुंभ जितना ही भव्य और दिव्य" होगाः *सीएम धामी*

अर्धकुंभ की तैयारी केवल धार्मिक आयोजनों तक सीमित नहीं है। राज्य सरकार ने नए घाट बनाने और पुराने घाटों की मरम्मत के साथ-साथ गंगा-कॉरिडोर परियोजना, सड़कों, पार्किंग, ट्रैफिक व्यवस्था, कूड़ा प्रबंधन, शौचालय और सफाई व्यवस्था जैसी सुविधाओं का व्यापक प्लान तैयार किया है। धामी सरकार ने 82 नए पदों की मंजूरी दी है, ताकि मेले की तैयारियों, घाट-परिवर्तन, पुल-सड़क विकास और अन्य विकास कार्य समय पर पूरे किए जा सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी तैयारी अक्टूबर 2026 तक पूरी हो जाएं, ताकि 2027 तक आयोजन सुचारू और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। इस बार का अर्धकुंभ न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि यह पर्यटन, स्थानीय अर्थव्यवस्था और राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस बार अर्धकुंभ में तीन शाही/अमृत स्नान होंगे, जो आम स्नानों से विशेष रूप से भिन्न होंगे। श्रद्धालु इन स्नानों को जीवनभर याद रहने वाला अनुभव मानते हैं। पहली बार अर्धकुंभ को इस पैमाने पर पूर्ण कुंभ की भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। इस महापर्व में आधुनिक व्यवस्थाओं, सुरक्षा और सुविधा पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि श्रद्धालु, साधु-संत और आम लोग सभी सहज रूप से भाग ले सकें। आयोजकों का कहना है कि यह अर्धकुंभ न केवल धार्मिक महत्व रखेगा बल्कि हरिद्वार को विश्व का आध्यात्मिक केंद्र बनाने में भी योगदान देगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक के बाद कहा कि 2027 का अर्धकुंभ "पुर्ण कुंभ जितना ही भव्य और दिव्य" होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार पहली बार साधु-संतों के लिए शाही/अमृत स्नान आयोजित किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं और साधु-समुदाय दोनों के लिए यह मेला एक यादगार घटना बने। सीएम धामी ने यह भी कहा कि सरकार और अखाड़ा परिषद मिलकर इस मेला को पूरी तैयारी, आधुनिक प्रबंध और पारंपरिक गरिमा के साथ आयोजित कर रही है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन एवं अन्य व्यवस्थाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने भरोसा जताया कि सभी प्रयासों से 2027 अर्धकुंभ हरिद्वार में सांस्कृतिक व आध्यात्मिक गौरव का प्रतीक बनेगा।

दर्ज हुआ। कम-से-कम 30 संतों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद एक बड़ी स्वास्थ्य-विवाद खड़ी हुई। जांच में पाया गया कि लगभग 1 लाख कोविड-टेस्ट रिपोर्टें फर्जी थीं। यानी निजी एजेंसी द्वारा फर्जी नेगेटिव रिपोर्ट्स जारी की गई थीं। हालांकि मेला प्रशासन और राज्य सरकार ने आदेश दिए थे कि श्रद्धालुओं को 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं और आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट दिखानी होगी और मास्क सोशल-डिस्टेंसिंग आदि का पालन अनिवार्य था। बावजूद इसके, कोविड-प्रोटोकॉल का उल्लंघन और भीड़-त्रुटि ने मेला के दौरान संक्रमण वृद्धि को हवा देने का काम किया जिससे उस समय कोविड-रोधी चिंताएं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बना। साल 2021 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत थे। उन्होंने 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री का पद संभाला था। 10 मार्च 2021 तक वे इस पद पर रहे। इसके बाद तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे (10 मार्च 2021 से 2 जुलाई 2021 तक)। फिर 4 जुलाई 2021 से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने। 2021 के पूरे साल में उत्तराखंड में तीन मुख्यमंत्री रहे और कुंभ मेला 2021 के समय त्रिवेन्द्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत दोनों के कार्यकाल का हिस्सा था।

उत्तराखंड में खुली महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट की राह

उत्तराखंड में महिलाओं की भूमिका और उनकी कार्यक्षमता को नए आयाम देने की दिशा में धामी सरकार ने एक और बड़ा कदम उठा दिया है। राज्य सरकार द्वारा दुकानों और प्रतिष्ठानों में महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति देना न केवल रोजगार के नए द्वार खोलता है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि अब महिलाओं का योगदान सीमाओं में नहीं, बल्कि हर क्षेत्र में समान रूप से स्वीकार्य और महत्वपूर्ण है। तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में जहां महिलाएं शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासन, व्यापार और तकनीक तक हर मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, वहीं सरकार का यह निर्णय उनके सपनों और करियर को और मजबूती प्रदान करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नेतृत्व शैली में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दिए जाने का यह फैसला एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है। राज्य में दुकानों व प्रतिष्ठानों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली (रात नौ से सुबह छह बजे तक) कार्य करने की सशर्त छूट प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें महिला कर्मियों की सुरक्षा का पर्याप्त प्रविधान किया गया है। रात्रि पाली में महिला कर्मियों को कार्य में तभी लिया जा सकता है, जब उनसे पूर्व में लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई हो। नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति देकर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तराखंड महिलाओं को न केवल अवसर देगा, बल्कि वह माहौल भी देगा जिसमें वे बिना किसी बाधा के अपनी प्रतिभा और क्षमता को पूरी तरह से उभार सकें। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट

उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और रोजगार के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव करते हुए धामी सरकार ने ऐसा फैसला लिया है, जिसे राज्य में महिला सशक्तिकरण के नए दौर की शुरुआत माना जा रहा है। 26 नवंबर को कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए घोषित किया कि अब राज्य के सभी दुकान व प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत महिलाएं रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट शिफ्ट

में काम कर सकेंगी। यह निर्णय उन शर्तों के साथ लागू होगा जिनमें सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना, कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराना और महिला कर्मचारी की लिखित सहमति लेना शामिल है। यह बदलाव केवल एक प्रशासनिक या कानूनी संशोधन नहीं है, बल्कि तेजी से विकसित हो रहे उत्तराखंड को एक आधुनिक, संवेदनशील और प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में उठाया गया कदम है। आज जब देश में महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर और कार्य-परिस्थितियां लगातार बदल रही हैं, उत्तराखंड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य उन राज्यों में शामिल होना चाहता है जहां महिलाएं हर क्षेत्र में बराबर की भागीदार होंगी चाहे वह दिन की पारी हो या रात की। पिछले एक दशक में उत्तराखंड की महिलाएं कृषि, शिक्षा, उद्यमिता, पुलिस, सैन्य बलों, स्वास्थ्य और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दे चुकी हैं। पहाड़ की महिलाएं आज भी श्रम और आत्मनिर्भरता की मिसाल हैं। रिटेल सेक्टर, फूड सर्विसेज, अस्पताल, होटल, टूरिज्म, बीपीओ सेक्टर, ऑनलाइन सेवाएं और ई-कॉमर्स उद्योग ऐसे क्षेत्र हैं जहां नाइट शिफ्ट आम है और बड़े शहरों में बड़ी संख्या में महिलाएं इनमें काम करती हैं। उत्तराखंड में इन क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है, ऐसे में महिलाओं को रात की पारी में काम करने का अधिकार देना न केवल उन्हें रोजगार में ज्यादा हिस्सेदारी दिलाएगा बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान भी बढ़ेगा।

धामी सरकार का यह निर्णय महिला-सशक्तिकरण की दिशा में उन मौजूदा सरकारी पहलों से जुड़ता है जो महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई हैं। इसमें मिशन शक्ति, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का विस्तार, 30% आरक्षण, महिला उद्यमिता योजनाएं, मातृ-शक्ति केंद्रों की स्थापना, महिला सुरक्षा ऐप्स और पुलिस विभाग में महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने जैसे कदम पहले से शामिल हैं। रात में काम करने के अवसर के साथ सबसे महत्वपूर्ण पहलू सुरक्षा का होता है। सरकार के अनुसार, नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षा इंतजाम अनिवार्य होंगे। प्रत्येक संस्थान को निम्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी।

कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध, सीसीटीवी और निगरानी सिस्टम, सुरक्षित परिवहन सुविधा या आने-जाने की व्यवस्था, महिला की लिखित सहमति, रात में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नोडल अधिकारी, आपात स्थितियों में तुरंत संपर्क की सुविधा औरस्वास्थ्य एवं शौचालय संबंधी साफ-सुथरी सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होती हैं, तभी समाज और परिवार में उनकी स्थिति और निर्णय क्षमता दोनों मजबूत होती हैं। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर जैसे शहरों में नाइट-इकोनॉमी पहले से ही उभर रही है। होटल, टूरिज्म, हेल्थकेयर, कॉल सेंटर, ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट, मीडिया और ई-कॉमर्स उद्योगों में महिलाओं के लिए बड़ी संभावनाएं हैं। धामी सरकार का यह निर्णय उत्तराखंड की महिलाओं को नई दिशा, नए अवसर और नए अधिकार प्रदान करता है। यह कदम केवल कानून में बदलाव नहीं, बल्कि सोच में बदलाव है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड अब उन राज्यों में शामिल होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है जहां महिलाओं को समान अवसर, समान सुरक्षा और समान सम्मान के साथ काम करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। यह राज्य के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में महिलाओं की भागीदारी को नई ऊँचाइयों तक ले जाने वाला निर्णय है। उत्तराखंड आज वास्तव में एक नए, आधुनिक और प्रगतिशील समाज की ओर कदम बढ़ा रहा है, जहां महिलाएं केवल सहयोगी नहीं, बल्कि विकास की असली धुरी साबित होंगी।

मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े मुआवजा राशि को बढ़ाने का धामी सरकार का अहम निर्णय

कैबिनेट बैठक में धामी सरकार ने मानव-वन्यजीव संघर्ष से जुड़े मुआवजे राशि को बढ़ाने का अहम निर्णय भी लिया गया। हाल के वर्षों में पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में बाघ, गुलदार, हाथी और अन्य वन्यजीवों के बढ़ते दायरे के कारण मानव जीवन और कृषि दोनों पर खतरा बढ़ा है। कैबिनेट की बैठक में मानव-वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई। वन्यजीवों के हमले में मृत्यु पर अब 10 लाख रुपये की मुआवजा राशि दी जाएगी। यही नहीं, घायल व्यक्तियों के उपचार का संपूर्ण खर्च भी सरकार उठाएगी। नए निर्णय के अनुसार मृत्यु, गंभीर घायल और आंशिक घायल होने की स्थितियों में मुआवजे की राशि पहले से अधिक की गई है, ताकि प्रभावित परिवारों को त्वरित आर्थिक राहत मिल सके। इसके अलावा कैबिनेट ने वन्यजीव संरक्षण, निगरानी, ट्रैकिंग और कानूनी कार्रवाई को मजबूत करने से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए कुछ अधिनियमों और नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई, जिससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सरल और प्रभावी बनेंगी। सरकार के अनुसार इन बदलावों से विभागों की कार्यक्षमता और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी, और राज्यस्तरीय नीतियों का तेजी से क्रियान्वयन संभव होगा। इन सब के साथ कैबिनेट के निर्णयों का एक व्यापक संदेश भी सामने आया है। धामी सरकार सामाजिक विकास, रोजगार के अवसर, सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों को एक साथ प्राथमिकता दे रही है। यह निर्णय केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि शासन की दिशा में एक साफ राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है कि सरकार जनहित, महिलाओं की सुरक्षा, वन क्षेत्रों की चुनौतियों और आम जनता के मुद्दों पर सक्रिय है। मानव-वन्यजीव संघर्ष में मुआवजा वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक राहत और भरोसा पैदा करेगी। दोनों मिलकर यह दिखाते हैं कि सरकार का फोकस सामाजिक संरक्षण, रोजगार विस्तार और संवेदनशील मुद्दों पर ठोस कार्रवाई पर है। इन फैसलों के लागू होने के बाद उनका प्रभाव आने वाले महीनों में प्रदेश की कार्यसंस्कृति, लैंगिक संतुलन, ग्रामीण सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता पर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड इन कदमों के साथ न केवल प्रगतिशील नीतियों की ओर बढ़ रहा है, बल्कि भविष्य के लिए अधिक संवेदनशील, सुरक्षित और सशक्त समाज का निर्माण करने की दिशा में भी मजबूत कदम उठा रहा है।

दिवाकर भट्ट:
आंदोलन की तपस्या से सत्ता की दहलीज तक, पहाड़ का एक जिद्दी सपूत

शीशपाल गुसाईं
वरिष्ठ पत्रकार

बड़ियारगढ़ की मिट्टी– जहाँ एक बच्चा जन्म लेता है, वहाँ की हवा ही उसकी आत्मा बन जाती है। दिवाकर भट्ट का बचपन भी उसी पहाड़ी हवाओं, उन्हीं कठिन ढलानों और उन्हीं सरल लोकजीवन के बीच पनपा। प्राथमिक शिक्षा पहाड़ की तलछट और लोकभूविज्ञान में डूबी हुई; और हाईस्कूल के बाद हरिद्वार की भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) में तकनीकी प्रशिक्षण। एक संयंत्रकर्मी के रूप में नौकरी पक्की हो चुकी थी– पर पहाड़ के बेटे की किस्मत में कारखानों की मशीनों से ज्यादा आंदोलन की मशालें थीं। जो रास्ता रोजगार ने खोला, उसे भाग्य ने मोड़ दिया।

दिवाकर भट्ट– उत्तराखंड राज्य आंदोलन का वह नाम, जो किसी ऊँचे देवदार के पेड़ की तरह था। हवा का कोई झोंका हो, संघर्ष का कोई मोर्चा हो, भीड़ कितनी ही व्यस्त क्यों न हो– उनकी उपस्थिति उनके चेहरे से नहीं, उनकी आवाज और प्रतिबद्धता से पहचानी जाती थी। 90 के दशक में उनकी ऊँचाई ऐसी थी कि आंदोलन के किसी भी मोर्चे पर खड़े होकर भी वे भीड़ में खोते नहीं थे– बल्कि भीड़ उनकी वजह से दिखती थी। पर विडंबना यह कि जिस राज्य के लिए उन्होंने जीवन का बड़ा हिस्सा खपा दिया, उसके गठन के बाद 2002 के पहले चुनाव में देवप्रयाग से UKD के प्रत्याशी के रूप में पराजय का सामना करना पड़ा। मानो पहाड़ की जीवनशैली का एक और सबक था– ऊँचा चढ़ने के लिए पहले एक गहरी घाटी उतरनी पड़ती है।

समय धीरे-धीरे पर्वतीय पगडंडियों की तरह आगे बढ़ता रहा। 2005–2006 में चंद्रकूट पर्वत पर जब परिसीमन का विवाद उठा, तो दिवाकर भट्ट फिर जनसरोकारों की अग्रिम पंक्ति में खड़े थे– इस बार भूख हड़ताल पर। वह हड़ताल उनकी तपस्या का पुनर्जन्म थी– जैसे आंदोलनकारी आत्मा फिर से जाग उठी हो। उन्हीं दिनों मैं सहारा टीवी के लिए चंद्रबदनी की कठिन चढ़ाई चढ़ रहा था। उनकी आँखों की आग, उनकी आवाज की दृढ़ता, उनकी भूख हड़ताल की तड़प– सब कैमरे में उतर रहा था। वे बेहद प्रसन्न थे। मुस्कुराकर बोले– "पहाड़ में सच दिखाने वाला पहला चैनल तुम लोग ही तो हो।" सच में, उस समय सहारा टीवी पर्वतीय अंचल का पहला 24 घंटे प्रसारित होने वाला चैनल था और दिवाकर जैसे आंदोलनकारियों को पहली बार जनता तक अपना सच सीधे पहुँचाने का मंच मिला था।

इसी दौर में उनके जीवन में एक ऐसा आघात आया जिसने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया– उनकी धर्मपत्नी का आकस्मिक निधन। दुःख इतना गहरा कि मानो किसी पहाड़ की चोटी अचानक खिसककर घाटी में समा गई हो। लेकिन उसी शोक ने लोगों के हृदयों को दिवाकर भट्ट से जोड़ दिया। लोग उन्हें एक राजनेता नहीं, एक अपना-सा आदमी मानने लगे– जो दुःख भी साझा करता है, और संघर्ष भी। शायद इसी संवेदना की धारा ने मिलकर उन्हें २००७ में देवप्रयाग भेजा– विधानसभा तक, जनता के प्रतिनिधि के रूप में। काउंटिंग वाले दिन मैं (बतौर प्रमुख पत्रकार सहारा टीवी) पूरे समय आईटीआई भवन नई टिहरी में उनके साथ था। दोपहर तक लोग उन्हें बधाई दे चुके थे, अन्य पांच विधायकों की उसी परिसर में काउंटिंग चल रही थी। लेकिन राजनीति कभी एकरेखीय नहीं चलती। जैसे-जैसे उत्तराखंड की टीवी पर राजनीतिक तस्वीर बदलती, वैसे-वैसे दिवाकर जी के चेहरे पर उम्मीद, संदेह और मुस्कान की हल्की किरणें आती-जाती रहीं। अंततः वही हुआ जिसकी वे मन ही मन चाह रखते थे– किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। हालांकि भाजपा को 35 सीटों का समर्थन था, लेकिन यूकेडी के 3 और निर्दलीय 3 विधायक सत्ता समीकरण में निर्णायक थे। दिवाकर भट्ट हमेशा कहते थे–" पहाड़ का स्वभाव ही मिश्रित सरकारों का है, जहाँ क्षेत्रीय दलों की भूमिका अनिवार्य होती है।" उसी चुनाव में नरेंद्रनगर से ओम गोपाल रावत भी उक्रांद से जीतेख़ टिहरी जनपद से दो-दो यूकेडी विधायक होना अपने आप में आंदोलन की जीत थी।

इसके बाद राजनीति ने उनके लिए एक नया अध्याय खोला। भुवन चंद्र खंडूड़ी पहले से ही उन्हें मंत्री बनाने के इच्छुक थे। वे कैबिनेट में एक अहम चेहरे के रूप में उभरे। पर राजनीति की हवा कभी स्थिर नहीं रहती– कभी शीतल, कभी तूफानी। 2009 में जब खंडूड़ी को हटाकर रमेश पोखरियाल 'निशंक'

को मुख्यमंत्री बनाने की हलचल शुरू हुई, तो कैंट रोड के राजनीतिक गलियारों में बेचैनी की धड़कनें सुनाई देती थीं। दिवाकर भट्ट धीमे स्वर में सिर्फ इतना बोले- "यह ठीक नहीं है, किसी मुख्यमंत्री को इस तरह बीच में हटाना..." लेकिन परिस्थितियाँ बदल गई, और निशंक ने भी उन्हें अपने मंत्रिमंडल में बरकरार रखा।

2011 में जब खंडूड़ी दोबारा मुख्यमंत्री बने, तब दिवाकर भट्ट तीसरी बार मंत्री बने। पाँच वर्षों में तीन बार शपथ लेना- यह किसी आंदोलनकारी के लिए अविश्वसनीय उपलब्धि थी। राजस्व से लेकर खाद्य विभाग तक, वे कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रभारी रहे। देवप्रयाग से देहरादून तक उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई।

2012 की दस्तक के साथ चुनाव फिर सामने था। भाजपा 'खंडूड़ी है जरूरी' के नारे के साथ उतरी। लंबे असमंजस के बाद दिवाकर भट्ट को टिकट मिला। वह शाम आज भी आँखों में तैरती है- वह अकेले ही भाजपा कार्यालय गए, टिकट लिया और शांत मन से लौट आए। पूरे जिले में हलचल फैल गई। पर राजनीति केवल टिकट का खेल नहीं- 2012 में उन्हें निर्दलीय मंत्री प्रसाद नैथानी से पराजय मिली, जो बाद में विजय बहुगुणा और हरीश रावत सरकारों के बेहद प्रभावशाली मंत्री बने।

इसके बाद 2017 और 2022- दोनों चुनाव उन्होंने उक्रांद के टिकट पर लड़े और दोनों में पराजित हुए। देवप्रयाग की धरती पर वे पाँच बार चुनाव लड़े- एक जीत और चार पराजय। लेकिन यह भी सच है कि यदि 2017 या 2022 जैसी भाजपा की भारी बहुमत की लहर 2007 में होती, तो शायद दिवाकर भट्ट कभी मंत्री ही न बन पाते। पर नियति कभी-कभी आंदोलनकारियों पर विशेष कृपा करती है- उन्हें वह मिलता है जो केवल चुनावी गणित से नहीं, संघर्ष की विरासत से तय होता है। राजनीति में उनके कदम पंचायतों से उठे थे। 1983 में वे कीर्तिनगर के ब्लॉक प्रमुख बने- और इतने लोकप्रिय कि लगभग दस वर्षों तक यह पद संभाला। 1996 में जिला पंचायत सदस्य बने। जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का सपना था, पर रतन सिंह गुनसोला और बलबीर सिंह नेगी का समीकरण भारी पड़ा और अध्यक्ष रतन सिंह गुनसोला बने, जिनकी आर्थिक पकड़ बहुत मजबूत मानी जाती थी।

उत्तराखंड क्रांति दल- राज्य आंदोलन की नींव रखने वाली पार्टी- आंतरिक कलह से बार-बार टूटती रही। सबसे बड़ा विभाजन दिसंबर 2010 में हुआ, जब भाजपा सरकार को बाहर से समर्थन देने के मुद्दे पर UKD दो हिस्सों में बंट गई। त्रिवेंद्र सिंह पंवार नेतृत्व में समर्थन वापस लेने का निर्णय हुआ, पर मंत्री दिवाकर भट्ट सत्ता में बने रहना चाहते थे। यहीं से UKD(P) और UKD(D) दो चेहरे बन गए। 2012 में चुनाव आयोग ने मूल नाम और प्रतीक 'कुर्सी' फ्रीज कर दिया। दोनों धड़ों ने अलग-अलग चुनाव लड़े, वोट बंट गए, और यूकेडी का जनाधार बिखरता चला गया। 2017 में एकता का प्रयास हुआ, मगर जीवन की कई दरारें जोड़ने के बाद भी पूरी तरह भर नहीं पातीं- वैसा ही कुछ पार्टी के साथ हुआ।

और फिर 25 नवंबर 2025- वह तारीख, जब हरिद्वार में 79 वर्ष की आयु में दिवाकर भट्ट इस दुनिया से विदा हो गए। उनका जाना केवल एक व्यक्ति का जाना नहीं- एक आंदोलनकारी परंपरा का टूटना था। यह यात्रा एक नेता की नहीं, एक तपस्वी की थी- जो भूख हड़ताल भी करता था, जेल भी देखी, पहाड़ के दुर्गम गाँवों में आंदोलन भी खड़े किए, और सत्ता में बैठकर मंत्रालय भी संभाले। उनका जीवन संघर्ष, अवसर, विडंबना और उपहार- इन चारों के मेल का अद्भुत दस्तावेज था। कठोर भी थे, कोमल भी। उग्र भी, संयमी भी। आंदोलनकारी भी, और मंत्री भी। दिवाकर भट्ट का जीवन उत्तराखंड की राजनीति का एक चलता-फिरता इतिहास था- बिना अलंकरण, बिना आडंबर, बिना विराम।

उन्होंने इस राज्य के लिए लाठियाँ खाईं, भूख सही, जनांदोलन उठाए, सत्ता में रहकर फैसले किए- और अपनी जिद, अपनी सरलता और अपने समर्पण से वह सम्मान पाया जिसे आज पूरा उत्तराखंड नम आँखों से याद कर रहा है। उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है- क्योंकि पहाड़ ने सिर्फ एक नेता नहीं खोया, बल्कि अपना एक जिद्दी, सच्चा, अदम्य सपूत खो दिया।

डीडीए निदेशक संदीप गुप्ता हुए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विशिष्ट सैन्य सम्मान से सम्मानित

डू समथिंग सोसाइटी की ओर से कण्वघाटी में चल रहे भरत महोत्सव के अंतिम दिन महोत्सव का उद्घाटन मुख्य अतिथि पद्मश्री डॉ. प्रेम चंद शर्मा ने किया। कार्यक्रम में डिफेंस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दून डिफेंस एकेडमी के निदेशक संदीप गुप्ता वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विशिष्ट सैन्य से सम्मान पुरस्कार किया गया।

वहीं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रहे 10 लोगों को सम्मानित किया गया।

इस मौके पर डीडीए निदेशक संदीप गुप्ता ने कहा कि आज का युवा नशे की गर्त में गिरता ही चला जा रहा है, जो उनके बढ़ते कदमों को रोक रहा है। अब समय है ऐसे युवाओं को सही मार्गदर्शन करने का। उन्होंने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि डू समथिंग सोसाइटी द्वारा आयोजित कार्यक्रम 'भारत नाम भरत महोत्सव' के सफल आयोजन के लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम के माध्यम से ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक दृष्टिकोण से महर्षि कण्व की तपस्थली एवं चक्रवर्ती सम्राट भरत की जन्मस्थली को केंद्रित करते हुए महिला सशक्तिकरण, बाल विकास, मधनिषेध व पलायन जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक विषयों के साथ छात्र-छात्राओं के बहुमुखी विकास हेतु खेलकूद प्रतियोगिता बहुत ही सराहनीय कार्य है।

इस मौके पर डू समथिंग सोसाइटी के अध्यक्ष मयंक प्रकाश कोठारी, संरक्षक आ. कै. दिगम्बर प्रसाद बलूनी, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी, पूर्व मेयर हेमलता नेगी, प्रकाश चंद्र कोठारी, आरपी पंत समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 देहरादून में संपन्न

हरिद्वार, पंतनगर एवं औली में स्थापित होंगे अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान राडारः डॉ. जितेंद्र सिंह

मुख्यमंत्री श्री धामी ने सिलक्यारा रेस्क्यू से लेकर हिमालय संरक्षण तक अनेक घोषणाएँ की

सम्मेलन में विज्ञान, तकनीक, शोध और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से आपदा प्रबंधन को सशक्त बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह की गरिमामयी उपस्थिति में देहरादून स्थित ग्राफिक एरा सिल्वर जुबली कन्वेंशन सेंटर में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन एवं 20वें उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन-2025 में बतौर विशिष्ट अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य डॉ. दिनेश कुमार असवाल की पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने वाली प्रतिभाशाली महिला वैज्ञानिकों को सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यभर के विभिन्न शोध एवं शैक्षणिक संस्थानों से चयनित वैज्ञानिकों को "Young Women Scientist Achievement Award–2025" तथा "UCOST Young Women Scientist Excellence Award" प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विज्ञान, अनुसंधान और तकनीक आधारित नवाचार आपदा प्रबंधन को सशक्त और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तराखंड की युवा महिला वैज्ञानिकों का शोध कार्य न केवल राज्य बल्कि देश और विश्व के लिए प्रेरण ादायक है।

सम्मानित वैज्ञानिकों में यंग वीमेन साइंटिस्ट अचीवमेंट अवार्ड-2025 (45 वर्ष तक) के अंतर्गत डॉ. अंकिता राजपूत, डॉ. गरिमा पुनेठा, डॉ. ममता आर्या, डॉ. हर्षित पंत, डॉ. प्रियंका शर्मा और डॉ. प्रियंका पांडे शामिल रहीं। वहीं यूकॉस्ट यंग वीमेन साइंटिस्ट एक्सीलेंस अवार्ड (30 वर्ष तक) के अंतर्गत डॉ. प्रियंका उनियाल, पलक कंसल, राधिका खन्ना, स्तुति आर्या तथा श्रीमती देवयानी मुंगल को सम्मानित किया गया।

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि इस विश्व आपदा सम्मेलन के आयोजन के लिए उत्तराखंड से बेहतर स्थान और कोई नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थानों के सहयोग से आयोजित यह सम्मेलन आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक दूरदर्शी और अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने घोषणा की कि हरिद्वार, पंतनगर और औली में अत्याधुनिक मौसम पूर्वानुमान राडार स्थापित किए जाएंगे, जो राज्य में मौसम संबंधी चेतावनी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाएंगे। डॉ. सिंह ने "सिलक्यारा विजय अभियान" का उल्लेख

करते हुए कहा कि इस अभियान ने सिद्ध किया कि दृढ़ इच्छाशक्ति, मजबूत नेतृत्व और वैज्ञानिक दक्षता किसी भी जटिल चुनौती को सफलतापूर्वक पार कर सकती है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उन्हें बताया गया है कि इस तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न हिमालयी राज्यों के प्रतिनिधि तथा देश-विदेश से आए वैज्ञानिक और शोधकर्ता हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों पर विस्तृत विचार-विमर्श करेंगे। साथ ही, तकनीकी नवाचार, अनुसंधान सहयोग तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में ठोस रणनीतियाँ बनाई जाएँगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस सम्मेलन से प्राप्त सुझाव और समाधान न केवल उत्तराखंड, बल्कि पूरे विश्व के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमालय केवल पर्वत श्रृंखला नहीं, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का जीवन स्रोत है। यहाँ की नदियाँ, ग्लेशियर और जैव विविधता पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, अनियंत्रित विकास और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से हिमालय का संतुलन प्रभावित हो रहा है। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बदलते मौसम पैटर्न, बढ़ती वर्षा की तीव्रता, अप्रत्याशित क्लाउडबर्स्ट और भूस्खलन की घटनाओं ने नई चिंता उत्पन्न की है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं और क्षेत्र विशेषज्ञों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इसी दिशा में यह विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन एक सेतु का कार्य करेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए "4P मंत्र-Predict, Prevent, Prepare और Protect" के आधार पर 10 सूत्रीय एजेंडा लागू किया गया है। इसका उत्कृष्ट उदाहरण सिलक्यारा सुरंग बचाव अभियान के दौरान देखने को मिला, जहाँ 17 दिनों के अथक प्रयासों से 41 श्रमिकों को सुरक्षित बचाया गया। यह अभियान आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। उन्होंने कहा कि इस अभियान के बाद राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को राहत एवं बचाव तक सीमित न रखते हुए वैज्ञानिक तकनीकों, जोखिम आकलन, एआई आधारित चेतावनी प्रणाली और संस्थागत समन्वय को मजबूत करने की दिशा में ठोस पहल की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लेशियर रिसर्च सेंटर, जल स्रोत संरक्षण कार्यक्रम और जनभागीदारी के माध्यम से हिमालय के दीर्घकालिक संरक्षण के प्रयास जारी हैं। उन्होंने बताया कि रैपिड रिस्पॉन्स टीमें गठित करने, ड्रोन सर्विलांस, जीआईएस मैपिंग, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और उच्च ऊँचाई वाले क्षेत्रों में सेंसर आधारित झील मॉनिटरिंग पर भी कार्य किया जा रहा है। साथ ही, अर्ली वार्निंग सिस्टम को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पौधारोपण,

"सिल्क्यारा विजय अभियान" आपदा प्रबंधन में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धि : केन्द्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव

देहरादून में आयोजित विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन-2025 में केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रतिभागियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि 'अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संस्थानों के सहयोग से आयोजित यह सम्मेलन आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल है। पिछले 25 वर्षों में राज्य ने चुनौतियों के बावजूद राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर एक प्रगतिशील पहचान स्थापित की है। उन्होंने सन्देश में कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का हिमालय से विशेष अनुराग रहा है और उन्होंने हिमालय के विषयों, सन्दर्भों, संरक्षण और सुरक्षा के विषयों को हमेशा से सामने रखा है। उन्होंने कहा कि हिमालय से निकली नदियाँ भारतीय सभ्यता की आधारशीला हैं। आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय पटल पर हिमालय को निरंतर केंद्र में रखने की आज आवश्यकता है। विश्वभर में जलवायु परिवर्तन और मानवजनित कारणों से आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसके लिए वैश्विक स्तर पर ठोस रणनीति की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित 10 सूत्रीय कार्यक्रम को विश्वभर में सराहनीय समर्थन प्राप्त हुआ है, जो भारत की नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलिजन फॉर डिजास्टर रेसिलेन्स इंफ्रास्ट्रक्चर (सीडीआरआई) जैसा वैश्विक संगठन बना है जो आपदा जैसे विषयों पर उत्कृष्ट कार्य कर रहा है।

श्री यादव ने कहा कि "सिल्क्यारा विजय अभियान" ने यह सिद्ध किया है कि कठिन परिस्थितियों में मजबूत इच्छाशक्ति, कुशल नेतृत्व और वैज्ञानिक दक्षता असंभव को संभव बना सकती है। यह अभियान विश्वभर के देशों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने हेतु विज्ञान एवं तकनीक आधारित आपदा न्यूनीकरण, पूर्वानुमान और पूर्व-तैयारी पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आधुनिक तकनीकों, अनुसंधान एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग से ही भविष्य की आपदाओं से समुचित रूप से निपटा जा सकता है।

अपने सम्बोधन के अंत में श्री यादव ने आशा व्यक्त की कि इस सम्मेलन से निकलने वाले विचार, शोध और सुझाव भारत सहित पूरे विश्व के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे तथा बहु-आपदा केंद्रित रणनीतियों के विकास में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएँगे। उन्होंने सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आयोजकों एवं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ भी दीं।

विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे उत्तराखण्ड कर रहा तेजी से प्रगति: रमेश पोखरियाल "निशंक"

देहरादून में 20वीं उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन के प्रारंभिक सत्र और विज्ञान प्रदर्शनी के उद्घाटन करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने राज्य की वैज्ञानिक प्रगति, शिक्षा तथा नवाचार में बढ़ती उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि ज्ञान-आधारित विकास ही उत्तराखण्ड के आगामी 25 वर्षों की दिशा तय करेगा। उन्होंने कहा कि प्रकृति के संकेतों को समझने की आवश्यकता है। एनडीएमए के सदस्य और मुख्य वक्ता डॉ. डी.के. असवाल ने उभरती प्रौद्योगिकियों, वैज्ञानिक मॉडलिंग और समुदाय-केंद्रित नीतियों की भूमिका को आपदा-रोधी समाज निर्माण के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि समुदायों को सुदृढ़ बनाकर ही आपदा प्रबंधन में विश्वस्तर पर पहचान बनाई जा सकती है। यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने कहा कि उत्तराखण्ड "देवभूमि" के साथ-साथ "युक्तिभूमि" भी है, और विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन व उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन जैसे मंच पूरी दुनिया के लिए समाधान देने में सक्षम हैं। आईटीडीए के निदेशक आलोक कुमार पाण्डे (आई.ए.एस.) ने आपदा प्रबंधन में डिजिटल उपकरणों और एआई आधारित प्रणाली के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हमें छोटी छोटी आपदाओं से सबक लेना चाहिए। राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय कुमार रुहेला ने संस्थागत समन्वय और समुदाय आधारित तैयारी को पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अनिवार्य बताया। इस अवसर पर सम्मेलन की विवरणिका का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर विज्ञान प्रोद्योगिकी सम्मेलन के आयोजन सचिव डॉ डीपी उनियाल ने स्वागत उद्बोधन दिया। इस अवसर पर विभिन्न वैज्ञानिक और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक, शोधार्थी और राज्य के सभी ब्लॉक से आए विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया।

जल संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रमों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सौर ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्प्रिंग रिजुविनेशन अथॉरिटी (SARA) का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक जल स्रोतों का चिन्हीकरण और पुनर्जीवन कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में 'डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम' लागू किया गया है, जिसके माध्यम से प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन में उल्लेखनीय सफलता मिली है और अब तक हिमालयी क्षेत्र में 72 टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है। इसी प्रकार अपनाए गए नवाचारों का परिणाम है कि नीति आयोग के एसडीजी इंडेक्स में उत्तराखंड को देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सनातन संस्कृति में प्रकृति को माँ के रूप में पूजने की परंपरा है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आस्था, परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को साथ लेकर आगे बढ़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जैव-विविधता और पर्यावरण ीय संतुलन को सुरक्षित रखने के अपने 'विकल्प-रहित संकल्प' के साथ निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह सम्मेलन आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में विश्व को नई दिशा प्रदान करेगा।

कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, सचिव नितेश झा, यूकॉस्ट महानिदेशक दुर्गेश पंत, ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय के चेयरमैन कमल घनशाला, विभिन्न देशों के राजदूतगण, केंद्र एवं राज्य सरकार के अधिकारीगण, देश-विदेश से आए शोधकर्ता, विषय विशेषज्ञ तथा ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय परिवार के सदस्य एवं छात्र उपस्थित रहे।

हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र पर केंद्रित रहा विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन: प्रो. दुर्गेश

यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत ने बताया कि विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मेलन तथा २०वाँ उत्तराखण्ड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सम्मेलन का आयोजन हिमालयी क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए वैश्विक विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिक संस्थानों, नवोन्मेषकों, युवा नेतृत्व, आपदा प्रतिक्रिया एजेंसियों और समुदाय प्रतिनिधियों को एक मंच पर लाकर भारत की वैज्ञानिक प्रणाली और आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण है।

उत्तराखण्ड का प्रथम राज्य-स्तरीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रीमियर लीग 2025 भी इसी अवसर पर आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य विज्ञान जागरूकता, जलवायु साक्षरता, नवाचार और आपदा तैयारी को राज्य के प्रत्येक गाँव तक पहुँचाना है। इसमें राज्य के सभी १३ जिलों से टीमें वैज्ञानिक क्विज, नवाचार प्रदर्शनी, आपदा प्रतिक्रिया चुनौतियों और जलवायु समस्या समाधान प्रतियोगिताओं में भाग लिया। यह पहल राज्य में बाल वैज्ञानिक और जलवायु प्रहरी तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। विश्व आपदा प्रबंधन शिखर सम्मलेन का मुख्य विषय, "समुदायों के निर्माण हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना", और 5E Framework (Engage, Educate,Enable, Empower, Excel) पर आधारित है। सम्मेलन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बढ़ती चुनौतियों जैसे बाढ़, भूस्खलन, वनाग्नि, हीटवेव, बादल फटना और हिमनद झील जोखिम का समाधान करना और भारत तथा हिमालयी क्षेत्र में वैश्विक सहयोग एवं ज्ञान साझा करने का मंच स्थापित करना है। सम्मेलन में छह प्रमुख प्लेनरी/ विचार विमर्श सत्र आयोजित किए गए, जिनमें आपदा प्रबंधन, जल संसाधन एवं ग्लेशियर खतरे, मानवता की सुरक्षा, हिमालय के संरक्षक, बहु-आपदा जोखिम, तथा पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से जागरूकता शामिल हैं। इसके अलावा बारह विशेष प्रौद्योगिकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें नीति, शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय साझेदारी, तकनीकी नवाचार, वित्तीय समाधान और हिमालयन कॉरिडोर लचीलापन से जुड़ी पहलें शामिल हैं।

पेपर लीक में प्रोफेसर समेत तीन गिरफ्तार

उत्तराखंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा पेपर लीक कांड में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टिहरी गढ़वाल के शहीद श्रीमती हंसा धनाई राजकीय महाविद्यालय की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को दो निजी आरोपियों, मोहम्मद खालिद और उसकी बहन सबीहा के साथ गिरफ्तार कर लिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि परीक्षा के दौरान प्रोफेसर सुमन ने प्रश्नपत्र के हिस्से हल कर आरोपी को भेजे थे। मोबाइल और अन्य डिजिटल सबूतों की कड़ियों ने उनकी भूमिका को स्पष्ट किया, जिसके बाद शुक्रवार, 28 नवंबर को गिरफ्तारी की गई। मामला सीबीआई के हाथ आने के बाद जांच तेज हो गई है और एजेंसी रोजाना नए तथ्य सामने ला रही है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट

उत्तराखंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा पेपर लीक मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए टिहरी गढ़वाल के शहीद श्रीमती हंसा धनाई राजकीय महाविद्यालय, अगरोरा (धार मंडल) की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को गिरफ्तार कर लिया। प्रोफेसर पर इस प्रकरण में शामिल दो निजी आरोपियों मोहम्मद खालिद और उसकी बहन सबीहा के साथ मिलीभगत कर पेपर लीक और समाधान उपलब्ध कराने का आरोप है। पेपर लीक की जांच पहले उत्तराखंड सरकार के पास थी, लेकिन मामला गंभीर होते देख इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। इसके बाद एजेंसी ने मोहम्मद खालिद और सबीहा को पुलिस हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की। हिरासत के दौरान मिले तकनीकी सबूतों, मोबाइल डेटा और बातचीत के आधार पर जांच का दायरा सुमन तक पहुंचा, जिसके बाद शुक्रवार 28 नवंबर को सीबीआई ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल जांच के बाद सभी आरोपियों को निर्धारित न्यायालय में पेश किया जाएगा। जांच में सामने आया है कि परीक्षा के दौरान सुमन को अपनी बहन के माध्यम से प्रश्नपत्र के कुछ हिस्से पहले ही मिल गए थे। उन्होंने इन प्रश्नों को हल कर तत्काल परीक्षा केंद्र में बैठे आरोपी प्राइवेट व्यक्ति तक पहुंचाया, जिससे उम्मीदवार नकल कर सकें। सीबीआई के अनुसार यह पूरी कार्रवाई योजनाबद्ध साजिश का हिस्सा थी, जिसमें आरोपी आपस में लगातार संपर्क में थे। एजेंसी की ओर से कहा गया है कि पेपर लीक कांड की तह तक पहुंचने के लिए पूछताछ और डिजिटल फोरेंसिक जांच रोजाना आधार पर जारी है, और आने वाले दिनों में और नाम सामने आने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि सितंबर में उत्तराखंड की ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर पेपर लीक का मामला उस समय उजागर हुआ था, जब परीक्षा के दिन ही कुछ अभ्यर्थियों के मोबाइल फोन से प्रश्नपत्र और समाधान के स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे। शुरुआती जांच में यह पता चला कि प्रश्नपत्र परीक्षा शुरू होने से करीब एक घंटे पहले ही सोशल मीडिया ग्रुप्स में पहुंच चुका था। इस खुलासे के बाद राज्य पुलिस तथा एसटीएफ ने रातोंरात कई जिलों में छापेमारी कर नकल कराने वाले सिंडिकेट के कई महत्वपूर्ण संचालकों को हिरासत में लिया था। जांच में सामने आया कि लीक हुआ प्रश्नपत्र कई व्हाट्सऐप ग्रुप्स में बेचा गया था, जिनमें उत्तराखंड के अलावा यूपी और दिल्ली के अभ्यर्थी भी जुड़े थे। पैसे यूपीआई और नकद दोनों रूपों में लिए जा रहे थे। कुछ अभ्यर्थियों ने स्वीकार किया था कि उन्होंने पेपर की 'कुंजी' परीक्षा केंद्र के अंदर ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए प्राप्त की थी। एसटीएफ ने उन डिवाइस विक्रेताओं तक भी अपनी जांच बढ़ाई, जो पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं में पकड़े गए थे। जांच के दौरान खालिद और उसकी बहन सबीहा के नाम पहली बार सामने आए थे। दोनों पर पेपर की कॉपी अलग-अलग चौनलों से अभ्यर्थियों तक पहुंचाने का संदेह जताया गया था। तब ही पुलिस ने इन दोनों को संदिग्ध मानकर उनके फोन, चौट बैकअप और बैंक लेन-देन को कब्जे में लिया था। कई डिजिटल साक्ष्य मिलने के बाद राज्य सरकार ने प्रकरण को बेहद संवेदनशील मानते हुए इसे सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया था। शुरुआती जांच ने यह संकेत दे दिया था कि पेपर लीक का यह मामला किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक संगठित नेटवर्क था, जो भर्ती परीक्षाओं के जरिए करोड़ों रुपये कमाने के प्रयास में जुटा था। कई कॉलेजों और परीक्षा केंद्रों से जुड़े लोग भी संदेह के घेरे में आए थे।

इसके बाद प्रदेश भर में आंदोलन शुरू हो गया। काफी लंबे समय तक बेरोजगार संगठन के लोग देहरादून के परेड ग्राउंड के बाहर धरने पर बैठे रहे। फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगभग 8 दिन के बाद छात्रों से मिलने उनके धरना स्थल पर पहुंचे थे और उन्होंने सीबीआई जांच की बात कही। इसके बाद सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को लिख दिया था। छात्रों ने दूसरी मांग अपनी की थी कि इस परीक्षा को रद किया जाए और उसका रोस्टर दोबारा से जारी किया जाए। छात्रों के बढ़ने प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन

किया, जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यूसी ध्यानी को सौंपी गई। इस आयोग को परीक्षा में हुई अनियमितताओं, पेपर लीक की प्रक्रिया, शामिल अधिकारियों और बाहरी नेटवर्क की भूमिका की जांच का अधिकार दिया गया था। आयोग ने कई जिलों में जाकर छात्रों, अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जनसंवाद किया और उन्हीं बयानों के आधार पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। छात्रों की मांग थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से करवाई जाए और परीक्षा को रद्द किया जाए। एकल सदस्यीय जांच आयोग की कई बैठकों में भी छात्रों ने इन मांगों को उठाया था। वहीं, जब आयोग ने रिपोर्ट सीएम धामी को सौंपी तो इसके कुछ ही घंटों बाद सरकार ने ये रिपोर्ट यूकेएसएसएसी को सौंपी। और फिर इस रिपोर्ट के आधार पर ही यूकेएसएसएसी ने परीक्षा को रद्द कर दिया था।

पेपर लीक नेटवर्क पर सीबीआई की कार्रवाई तेज, कई परीक्षा केंद्रों की निगरानी सूची तैयार

उत्तराखंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा पेपर लीक कांड के बाद सीबीआई अब राज्यभर में फैले नकल सिंडिकेट के नेटवर्क को खंगालने में जुट गई है। एजेंसी ने बीते एक सप्ताह में कई जिलों के परीक्षा केंद्रों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों से जुड़े शिक्षकों व स्टाफ की भूमिका की प्रारंभिक मैपिंग पूरी कर ली है। सीबीआई ने उन केंद्रों की एक विस्तृत निगरानी सूची तैयार की है, जहां पिछली परीक्षाओं में डिजिटल डिवाइस, व्हाट्सऐप ग्रुप और प्रॉक्सी के जरिए नकल कराने की शिकायतें सामने आई थीं। सीबीआई ने कुछ परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग को भी अपने कब्जे में लिया है। कई कर्मचारियों को नोटिस भेजकर बयान तलब किए गए हैं। एजेंसी यह भी जांच कर रही है कि पेपर लीक नेटवर्क केवल मौजूदा परीक्षा तक सीमित था या पिछले वर्षों की भर्ती परीक्षाएं भी इसकी चपेट में थीं। बताया जा रहा है कि जांच टीम ने उन ठिकानों पर भी दस्तक दी है, जहां से नकल के उपकरण जैसे माइक्रो ईयरपीस, ब्लूटूथ डिवाइस और हाई-रेंज सिग्नल ट्रांसमीटर पिछले मामलों में बरामद हुए थे। इन उपकरणों की बिक्री करने वालों से भी पूछताछ की जा रही है। सीबीआई का कहना है कि शुरुआती जांच में कई संदिग्ध लेन-देन और डिजिटल ट्रेल मिले हैं, जो इस रैकेट के और बड़े रूप की ओर संकेत करते हैं। एजेंसी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में इस मामले में कई और गिरफ्तारी हो सकती है।

उत्तराखंड को बड़ी सौगात, कृषि मंत्री गणेश जोशी के आग्रह पर जल्द राज्य में खुलेंगी खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के टेस्टिंग लैब

नई दिल्ली में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड बैठक में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने किया प्रतिभाग

बैठक के दौरान कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड के निर्यात क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों को रखते हुए मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के परीक्षण के लिए एपिडा की परीक्षण प्रयोगशाला को उत्तराखंड में स्थापित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यदि राज्य में ही जांच सुविधा उपलब्ध हो जाए, तो कृषि उत्पादों की निर्यात गुणवत्ता और विश्वसनीयता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से अनुरोध करते हुए कहा कि राज्य में अभी तक विदेशी बाजारों में निर्यात होने वाले उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप जांच के लिए कोई उन्नत टेस्टिंग लैब उपलब्ध नहीं है। विशेष रूप से फल, सब्जी और अन्य खाद्य प्रसंस्करण उत्पादों के परीक्षण के लिए आधुनिक लैब न होने से निर्यात प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है और किसानों व निर्यातकों को चंडीगढ़, लखनऊ, गाजियाबाद सहित अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे समय और धन दोनों की हानि होती है और प्रतिस्पर्धी बाजारों में उत्तराखंड के उत्पादों को अतिरिक्त चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

कृषि मंत्री गणेश जोशी के इस अनुरोध को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक में उपस्थित एपिडा अधिकारियों को तुरंत निर्देशित किया कि उत्तराखंड को आयात- निर्यात प्रक्रिया में आ रही कठिनाइयों को देखते हुए टेस्टिंग लैब की स्वीकृति प्रदान की जाए। मंत्री गणेश जोशी ने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार जताते हुए कहा कि इससे कृषक उत्पादों, विशेषकर फलों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बड़ा लाभ मिलेगा। मंगलवार को नई दिल्ली में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आयोजित बोर्ड ऑफ ट्रेड बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रतिनिधि के रूप में प्रतिभाग कर कहा कि मंत्री गणेश जोशी ने कि राज्य में निर्यात प्रोत्साहन नीति 2021 लागू है, जिसका लक्ष्य अगले पाँच वर्षों में निर्यात को 15,000 करोड़ से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाना है। वर्तमान में उत्तराखंड से मुख्य रूप से फार्मा, प्लास्टिक, केमिकल एवं ऑटोमोबाइल उत्पादों का UAE, USA और सिंगापुर सहित अन्य देशों को निर्यात किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि पंतनगर और काशीपुर में दो ICD संचालित हैं तथा हरिद्वार में एक नया ICD निर्माणाधीन है। निर्यात नीति 2021 और लॉजिस्टिक नीति 2023 ने राज्य की निर्यात क्षमता को मजबूत आधार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया अंब्रेला ब्रांड "हाउस ऑफ हिमालयास" उत्तराखंड के कृषि एवं उद्यानिकी उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दे रहा है।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत 'सिल्वर एलीफेंट अवार्ड' से सम्मानित

19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल के हाथों मिला सम्मान

कहा, स्काउटिंग अनुशासन, एकता और देशभक्ति का भाव विकसित का मंच

भारत स्काउट्ड एंड गाइड्स की 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के अवसर पर सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत को 'सिल्वर एलीफेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉ. रावत को यह सम्मान प्रदान किया। इस अवसर पर डॉ. रावत ने कहा कि स्काउटिंग युवाओं में अनुशासन, एकता और देशभक्ति का भाव विकसित करने का बड़ा मंच है, जिसका विस्तार प्रदेश के स्कूलों व कॉलेजों में निरंतर किया जा रहा है।

19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के अवसर पर उत्तर प्रदेश राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में आज (बुधवार) राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'सिल्वर एलीफेंट अवार्ड' से कैबिनेट मंत्री व डॉ. धन सिंह रावत को सम्मानित किया।

डॉ. रावत ने की सीएम योगी से मुलाकात लखनऊ में आयोजित भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की 19वीं जम्बूरी में प्रतिभाग करने पहुंचे सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर डॉ. रावत ने राष्ट्रीय जम्बूरी के भव्य व सफल आयोजन पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं बीच उत्तराखंड से जुड़े विभिन्न मुद्दों और समसामयिक विषयों पर सकारात्मक व सार्थक चर्चा हुई।

इस अवसर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉ. रावत द्वारा उत्तराखंड में स्काउट-गाइड आंदोलन को मजबूत करने, इसे व्यापक स्तर पर लागू करने तथा युवाओं में सकारात्मक व राष्ट्रनिर्माण की सोच विकसित करने हेतु किये गये प्रयासों की सराहना की और उन्हें शुभकामनाएं भी प्रेषित की।

राष्ट्रीय जम्बूरी में प्रदेश के युवाओं से की मुलाकात: भारत स्काउट एंड गाइड उत्तराखंड के प्रादेशिक अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज लखनऊ में आयोजित १९वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में प्रतिभाग कर रहे प्रदेश के स्काउट्स एंड गाइड्स दल से मुलाकात की। कार्यक्रम स्थल पर स्काउट्स गाइड्स ने डॉ. रावत का बैंड की धुन बजाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉ. रावत ने सभी प्रतिभागियों को जम्बूरी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दीं और कहा कि स्काउटिंग युवाओं में सेवा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता विकसित करती है।

सिल्वर एलीफेंट अवार्ड से सम्मानित होने पर डॉ. रावत ने कहा कि यह क्षण उनके लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि स्काउटिंग युवाओं में अनुशासन, एकता, सेवा-भाव और देशभक्ति की भावना को विकसित करने का सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के स्कूलों एवं कॉलेजों में स्काउट-गाइड गतिविधियों के विस्तार और उसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।

डॉ. रावत ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स संगठन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह संस्था देशभर में स्काउट-गाइड गतिविधियों के माध्यम से युवाओं के शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है साथ ही विश्वव्यापी भाईचारे की भावना को भी सशक्त बना रही है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान उन्हें भविष्य में और अधिक समर्पण के साथ जनसेवा व युवा सशक्तिकरण के कार्यों में जुटने की प्रेरणा प्रदान करेगा।

जनसंचार में नई ऊर्जा, सूचना तंत्र में नई धार, उत्तराखंड सूचना विभाग की निर्णायक पहल

सूचना तंत्र "रूटीन मोड" में नहीं चलेगा-यह तेज, पेशेवर और जनता-केंद्रित होगा- *बंशीधर तिवारी*

सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जिला सूचना अधिकारियों के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में यह साफ कर दिया कि अब सूचना तंत्र "रूटीन मोड" में नहीं चलेगा- यह तेज, पेशेवर और जनता-केंद्रित होगा। बंशीधर तिवारी की कार्यशैली की धार इसी में दिखती है कि वे सिर्फ निर्देश नहीं देते, बल्कि हर अधिकारी को यह अहसास कराते हैं कि सूचना विभाग सरकार की आवाज ही नहीं, जनता का भरोसा भी है।

उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजनाएँ तभी प्रभावी बनती हैं, जब उनकी सही, समयबद्ध और सटीक जानकारी जनता तक पहुँचे। इसी सोच के साथ उन्होंने जिला स्तर पर मीडिया संबंधों को और मजबूत करने, संवाद को सहज बनाने और पत्रकारों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

तिवारी के निर्देशों की धार-

* सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रचार रचनात्मक, तथ्य-आधारित और जिम्मेदाराना हो।
* जनता से जुड़ी सक्सेस स्टोरी और प्रेरक सामग्री नियमित रूप से सामने लाई जाए।
* किसी भी तरह की अपुष्ट, अधकचरी या भ्रामक सूचना से विभाग की विश्वसनीयता को आंच न आने दी जाए।

यह केवल बैठक नहीं थी यह विभाग की भविष्य की दिशा तय करने वाला संदेश था। स्पष्ट संकेत है कि बंशीधर तिवारी एक ऐसा सूचना तंत्र खड़ा करना चाहते हैं जो-

* तेज भी हो,
* विश्वसनीय भी हो,
* और पूरी तरह जनता की आवाज को केंद्र में रखने वाला भी। यही उनकी कार्यशैली की सबसे बड़ी शक्ति है साफ विजन, सख्त प्राथमिकताएँ और नतीजों पर सीधा फोकस।

पीआरएसआई डेलीगेशन ने मुख्यमंत्री से की शिष्टाचार भेंट, देहरादून में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए दिया आमंत्रण

पब्लिक रिलेशंस सोसाइटी ऑफ इंडिया (PRSI) के डेलीगेशन ने राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल के नेतृत्व में आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शिष्टाचार भेंट की। आगामी 13, 14 एवं 15 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने जा रहे राष्ट्रीय जनसंपर्क अधिवेशन के लिए मुख्यमंत्री को औपचारिक आमंत्रण दिया गया। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री को अधिवेशन का ब्रोशर भेंट करते हुए संस्था की गतिविधियों एवं उद्देश्यों की विस्तृत जानकारी दी।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस वर्ष अधिवेशन का मुख्य विषय "विकसित भारत @2047 में जनसंपर्क की भूमिका" निर्धारित किया गया है। सम्मेलन में देशभर के विभिन्न राज्यों से 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष को ध्यान में रखते हुए अधिवेशन में राज्य की विकास यात्रा, उपलब्धियों तथा भविष्य की संभावनाओं पर विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित विकसित भारत @2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में जनसंपर्क की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पर्यटन, संस्कृति एवं स्थानीय उत्पादों की प्रभावी ब्रांडिंग की दिशा में जनसंपर्क माध्यम अहम योगदान दे सकते हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के सकारात्मक उपयोग, जनता से सतत संवाद, फेक न्यूज की रोकथाम तथा मीडिया-जनसंपर्क क्षेत्र में एआई के बढ़ते प्रभाव पर भी मंथन की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर पीआरएसआई देहरादून चैप्टर के अध्यक्ष रवि बिजारनिया, सचिव अनिल सती, कोषाध्यक्ष सुरेश भट्ट, संयोजक सिद्धार्थ बंसल, सदस्य वैभव गोयल, अनिल वर्मा, अजय डबराल, संजय भार्गव और प्रियांक वशिष्ठ भी उपस्थित रहे।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

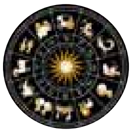
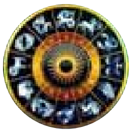
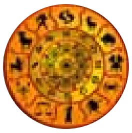

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि– आर्थिक गतिविधियों से संबंधित कुछ लाभकारी योजनाएं बनेंगी और वह तुरंत क्रियान्वित भी हो जाएंगी। प्रेम संबंध में भी किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की आशंका है। कोई भी निर्णय बहुत अधिक सोच समझकर लेने का प्रयास करें। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करें। भाग्यशाली रंग– क्रीम, भाग्यशाली अंक– 5

वृषभ राशि– परिवार में बड़े बुजुर्गों का स्नेह और आशीर्वाद बना रहेगा। घर में कोई धार्मिक आयोजन संबंधी कार्य भी संपन्न होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आय के साथ साथ खर्चे भी बने रहेंगे। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। घर में भी आपसी प्रेम और सौहार्द बना रहेगा। आयुर्वेदिक इलाज इसके लिए सर्वोत्तम है। भाग्यशाली रंग– पीला, भाग्यशाली अंक– 3

मिथुन राशि– सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति से प्रतिष्ठा और मान सम्मान रहेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाएं। व्यवसायिक कार्यप्रणाली को बेहतर करने के लिए मनन व चिंतन करें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाग्यशाली रंग– आसमानी, भाग्यशाली अंक– 4

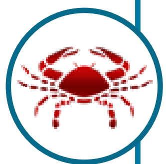

कर्क राशि– महिलाएं अपने क्षेत्र में वर्चस्व हासिल करेंगी। नौकरी में स्त्रियों को विशेष सफलता हासिल होगी। वाणी पर संयम रखने से घर में सुख शांति रहेगी। दूसरों के मामले में ज्यादा हस्तक्षेप करने से बचें। दाम्पत्य संबंधों में कुछ मनमुटाव रह सकते हैं। योग और ध्यान भी प्रभावी रहेगा। भाग्यशाली रंग– आसमानी, भाग्यशाली अंक– 8

सिंह राशि– घर में कोई धार्मिक आयोजन भी संभव है। आपके नेतृत्व में कोई विशेष गतिविधि संपन्न होगी। बच्चों पर कठोर नियंत्रण न करके उन्हें अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्रता दें। परिवार के साथ किसी उत्सव आदि में जाने का मौका मिलेगा। घर के किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रहेगी। लापरवाही बिल्कुल न करें। भाग्यशाली रंग– गुलाबी, भाग्यशाली अंक– 3

कन्या राशि– अपने लक्ष्य को हासिल करने का उत्तम समय है। संतान को भी कोई उपलब्धि मिलने से घर में खुशी भरा वातावरण रहेगा। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। किसी भी तरह की लेनदेन संबंधी गतिविधियों से बचें। अत्यधिक खर्चे भी परेशान करेंगे। प्रेम संबंधों को जाहिर करने के लिए अभी धैर्य रखें। भाग्यशाली रंग– केसरिया, भाग्यशाली अंक– 9

तुला राशि– अपनी आर्थिक योजनाएं सफलतापूर्वक संपन्न कर सकेंगे। युवा मेहनत और योग्यता से निश्चित ही सफलता हासिल करेंगे। अनुभवी तथा वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन और सलाह पर जरूर अमल करें। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है। व्यर्थ की गतिविधियों में समय नष्ट न करें। भाग्यशाली रंग– हरा, भाग्यशाली अंक– 2

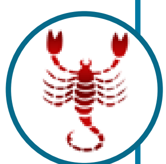

वृश्चिक राशि– आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। घर में सुख शांति भरा माहौल रहेगा। किसी भी गतिविधि को अपनी देखरेख में ही करवाना उचित है। अजनबी लोगों पर विश्वास करना नुकसान दे सकता है। घर में सुख शांति रहेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आप अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा महसूस करेंगे। भाग्यशाली रंग– नीला, भाग्यशाली अंक– 7

धनु राशि– संपत्ति संबंधी खरीद बिक्री कोई गतिविधि से संबंधित कुछ विचार विमर्श हो सकते हैं। व्यर्थ के क्रोध से बचें। विदेशी संबंधों से भी लाभ होगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। घर के किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है। आपकी देखरेख से जल्दी ही स्वास्थ्य में सुधार आएगा। भाग्यशाली रंग– गहरा लाल, भाग्यशाली अंक– 1

मकर राशि– पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी। अपने ऊपर काम की उतनी ही जिम्मेदारी लें जितनी कि आप आसानी से निभा सकें। मेहनत के अनुरूप उचित परिणाम भी हासिल नहीं होंगे। पति पत्नी में कुछ टकराव आ सकता है। पारिवारिक व्यवस्था सुखद बनी रहेगी। नियमित प्राणायाम करें और मौसम के अनुकूल आहार लें। भाग्यशाली रंग– हरा, भाग्यशाली अंक– 1

कुंभ राशि– निवेश संबंधी योजना पर विचार हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम को बखूबी अंजाम दे पाएंगे। छात्र तथा युवा वर्ग अपने लक्ष्य से न भटकेँ। ग्रह स्थिति भी बहुत अधिक उत्तम नहीं है। सावधानी बरतना अति आवश्यक है। परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना जरूरी है। भाग्यशाली रंग– लाल, भाग्यशाली अंक– 6

मीन राशि– किसी सरकारी कार्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तरीके से संपन्न होने की संभावना बन रही है। घर के बदलाव संबंधी कोई कार्य भी संभव हो सकता है। महिलाएं अपने दायित्व को बखूबी निभाएंगी। विवाहित व्यक्तियों का ससुराल पक्ष से कुछ मनमुटाव होने जैसी स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान दें। भाग्यशाली रंग– आसमानी, भाग्यशाली अंक– 5

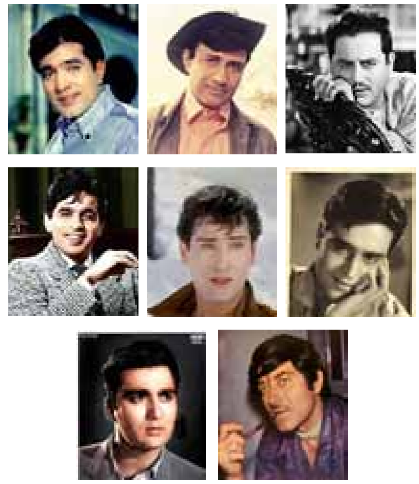

'नहीं रहे 'ही मैन', 89 की उम्र में धर्मेन्द्र का निधन'

धर्मेंद्र की पंजाबी भाषा में लिखी हुई इमोशनल कविता, उनकी ही आवाज में सुनाई दे रही है। जिसमें धर्मेंद्र कह रहे हैं- 'आज भी मन करता है...अपने गांव जाऊं, तालाब में घुसकर, भैंसों को नहलाऊं। हंसिया (दराती) लेकर खेतों से, चारा भी लाऊं। मिट्टी में कबड्डी वाला खेल खेलना, गांव वाली जिंदगी का किससे मेल (तुलना)। पांच नदियों (पंजाब) का मीठा-मीठा पानी, बहती हवाओं में गुरुओं की वाणी। मुश्किल है, मां की गोद (आंचल) को मन से भुलाना। हां ओ मेरी मां, मैं तुझ पर बलिहारी जाऊं। आज भी मन करता है अपने गांव जाऊं... आज भी मन करता है अपने गांव जाऊं।

24 नवंबर को हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र ने इस दुनिया को हंसते हुए अलविदा कह दिया। सुपरस्टार धर्मेंद्र को फिल्म इंडस्ट्री का ही-मैन कह कर बुलाया जाता है। उनका जन्म 1935 को हुआ था और 2025 में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक्टर ने गुड्डी, धरम वीर, शोले, अपने, मेरा गांव मेरा देश, सत्यकाम और शिकार जैसी फिल्मों में काम किया था। धर्मेंद्र ने अपनी पूरी जिंदगी मस्तमौला अंदाज में जी और सभी लोगों को हमेशा खुश रहने की सलाह दी। पर्सनल से लेकर प्राफेशनल तक वो काफी जिंदादिल इंसान थे। एक परफेक्ट एक्टर होने के साथ ही साथ वो शानदार कलमकार थे। जिसकी छोटी सी झलक फिल्म 'इक्कीस' में देखने को मिली, यह उनकी आखिरी फिल्म थी, जिसे श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है। बॉलीवुड का इतिहास बहुत लंबा हो चला है। इस दौरान कई सारे स्टार्स इस इंडस्ट्री का हिस्सा रहे और फैंस को एंटरटेन करते नजर आए। कई स्टार्स तो ऐसे हैं जो अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। हाल ही में बॉलीवुड के ही-मैन का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। बॉलीवुड के इतिहास में एक से बढ़कर एक एक्टर्स आए हैं जिन्होंने इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया और दुनियाभर की जनता से उन्हें ढेर सारा प्यार भी मिला। वे देखते ही देखते लोगों के जीवन का हिस्सा बन गए और दिलों में राज भी किया। ऐसे ही एक एक्टर थे धर्मेंद्र। उन्होंने भी इंडस्ट्री में 6 दशक से ज्यादा का समय तय किया और अब जब वो इस दुनिया में नहीं हैं तो जनता उन्हें याद कर रही है। बॉलीवुड ने एक ऐसा दिग्गज खो दिया है जिससे इंडस्ट्री में एक बड़ा शुन्य पैदा हो गया है। लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इंडस्ट्री में ऐसा शुन्य पैदा हुआ हो। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर की बात करे तो इन दिग्गजों ने दुनिया को अलविदा कहा। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार राज कपूर को इंडस्ट्री में शोमैन के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म साल 1924 में हुआ था और साल 1988 में उनका निधन हो गया था। उन्होंने कई फिल्मों में एक्टिंग की और शानदार फिल्मों का निर्देशन भी किया। आग, संगम, मेरा नाम जोकर, अनारी श्री 420 और आवारा जैसी फिल्मों का वे हिस्सा रहे। दीलीप कुमार को इंडस्ट्री में ट्रैजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। उनका जन्म साल 1922 में हुआ था और एक्टर का निधन कुछ साल पहले ही साल 2021 में हुआ था। वे देवदास, नया दौर, गोपी, राम और श्याम, विधाता जैसी फिल्मों में नजर आए थे।

गुरु दत्त फिल्म इंडस्ट्री के ऑल राउंडर थे। उनका जन्म साल 1925 में हुआ था और साल 1964 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। गुरु दत्त ने प्यासा, कागज के फूल, आर पार, बाजी, चौदवीं का चांद, सीआईडी और जाल जैसी फिल्मों में काम किया था। राजेश खन्ना को इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार माना जाता है और जैसी पॉपुलैरिटी और क्रेज उन्हें लेकर था वैसा किसी और को लेकर देखने को नहीं मिला। उनका जन्म साल 1942 में हुआ था और साल 2012 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। इंडस्ट्री में देव आनंद को सदाबहार एक्टर के तौर पर जाना जाता था। वे उन कलाकारों में से एक रहे जिन्होंने अंतिम सांस तक काम किया। साल 2011 में उनका निधन हो गया था। राज कुमार की बात करें तो एक्टर का जन्म 1926 में हुआ था और उन्होंने साल 1996 में अंतिम सांस ली थी। उन्हें आज भी उनके डायलॉग्स और स्टाइल की वजह से याद किया जाता है।

संजय दत्त के पिता सुनील दत्त का फिल्मी और पॉलिटिकल करियर दोनों ही काफी हिट रहे। साल 2005 में 75 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली थी। एक्टर राजेंद्र कुमार को इंडस्ट्री में जुबली किंग के तौर पर जाना जाता था। एक्टर का जन्म साल 1927 में हुआ था और 1999 में उनका निधन हो गया था। शम्मी कपूर को फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट हैंडसम एक्टर में से एक माना जाता है। उन्होंने 79 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Silkyara™

A2 Protein

Ancient Bellona Method

Beneficial for Health

Hamari Pahad Ki Matao Dwara
Pyar se Banaya Gaya

BADRI COW GHEE

fssai
22623030001586

Available on

Kumar Sweets

- *Sahastradhara Road, Near Crossing*
- *Dharampur Near LIC Building*

Dehradun